Revisiting dam-induced displacement:
A capabilities approach to socio-spatial justice

Muzamil Yaqoob

School of Public Policy

INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY DELHI

2026

Thesis Abstract

Despite significant critique, the processes of resettlement and rehabilitation (R&R), due to dam-induced displacement, continue to remain transactional and based on material equivalence. This study aims to understand how people displaced by dam projects have experienced the processes of R&R. It critically examines the existing policy landscape grounded in frameworks that are primarily focused on compensation and explores how a 'capabilities' approach to resettlement policies could lead to more just outcomes. Based on two case studies of rehabilitation in dam projects in Jammu and Kashmir, the study proposes a rehabilitation framework that integrates the enhancement of human capabilities.

This study examines how people displaced by hydropower projects experience rehabilitation and resettlement (R&R), and how a capabilities-based framework can lead to more just and sustainable outcomes. It questions the long-standing reliance on compensation-based rehabilitation mechanisms. It argues for a deeper understanding of how displacement transforms people's freedoms and their capability to live a meaningful life.

Development-induced displacement is one of the most pressing challenges of our time. Globally, tens of millions are displaced every year by infrastructure projects, yet most never regain their former well-being. In India, dams remain a significant cause of forced relocation, often affecting marginalized social groups. Despite policy evolution, from the 1894 Land Acquisition Act to the 2013 LARR Act, rehabilitation remains transactional and materialistic. The study contends that such approaches fail to recover the lost capabilities, the real freedoms that enable people to live lives they value, thereby perpetuating injustice and exclusion.

The research adopts a mixed-methods, qualitative-led design across two major hydropower projects: the Kishanganga dam project in Bandipora and the Pakal Dul project in the Kishtwar district of Jammu and Kashmir. Through over 40 in-depth interviews with people, 15 with

officials, 105 household surveys, and analysis of policy reports, rehabilitation plans etc, the study traces the institutional landscape, power structures, and lived experiences of displacement across the aforementioned sites. Phased fieldwork between 2022 and 2025 combined archival research, actor mapping, and community-level inquiry to triangulate insights from policy, practice, and lived experience.

Field evidence suggests that R&R in regions like Jammu and Kashmir remains fragmented, bureaucratically driven, and largely inattentive to the socio-spatial realities of affected communities. Displacement erodes not only livelihoods and housing but also social cohesion, ecological belonging, and psychological well-being. Women and vulnerable individuals bear disproportionate burdens, while participation in decision-making remains tokenistic. By linking spatial dimensions with the ability to convert benefits into real opportunities, the study demonstrates that justice is not only about what people receive but where and how they can rebuild their lives.

While earlier research and policy reports have called for more humane and participatory approaches to rehabilitation, this study makes a distinctive contribution by demonstrating how such justice can be realised in practice through a capability- and spatially informed policy approach across various developmental contexts, both nationally and globally.

Abstract in Hindi

काफी आलोचनाओं के बावजूद, बांधों के कारण होने वाले विस्थापन में पुनर्वास और पुनर्स्थापन (R&R) की प्रक्रियाएँ अब भी लेन-देन पर आधारित और केवल भौतिक मुआवज़े तक सीमित रहती हैं। यह अध्ययन समझने का प्रयास करता है कि बांध परियोजनाओं से विस्थापित लोगों ने पुनर्वास और पुनर्स्थापन की प्रक्रिया को किस प्रकार अनुभव किया है। यह मौजूदा नीतिगत ढांचे की आलोचनात्मक समीक्षा करता है, जो मुख्यतः मुआवज़े पर केंद्रित हैं, और यह खोजता है कि 'क्षमता दृष्टिकोण' (Capabilities Approach) पर आधारित पुनर्वास नीतियाँ किस प्रकार अधिक न्यायपूर्ण परिणाम दे सकती हैं। जम्मू और कश्मीर में दो बांध परियोजनाओं के पुनर्वास के केस स्टडी के आधार पर, यह अध्ययन एक ऐसा पुनर्वास ढांचा प्रस्तावित करता है जो मानवीय क्षमताओं के विकास को केंद्र में रखता है।

यह अध्ययन यह भी जांचता है कि जलविद्युत परियोजनाओं से विस्थापित लोग पुनर्वास और पुनर्स्थापन को कैसे अनुभव करते हैं, और किस प्रकार क्षमताओं पर आधारित ढांचा अधिक न्यायपूर्ण और टिकाऊ परिणाम दे सकता है। यह केवल मुआवज़े पर आधारित पुनर्वास व्यवस्था पर सवाल उठाता है। अध्ययन का तर्क है कि विस्थापन लोगों की स्वतंत्रताओं और उनके अर्थपूर्ण जीवन जीने की क्षमता को गहराई से प्रभावित करता है।

विकास के कारण होने वाला विस्थापन आज के समय की सबसे गंभीर चुनौतियों में से एक है। विश्व स्तर पर हर वर्ष लाखों लोग अवसंरचना परियोजनाओं के कारण विस्थापित होते हैं, और उनमें से अधिकांश लोग अपने पूर्व जीवन स्तर को दोबारा हासिल नहीं कर पाते। भारत में बांध अभी भी जबरन विस्थापन का एक बड़ा कारण हैं, जो अक्सर हाशिए पर रहने वाले सामाजिक समूहों को प्रभावित करते हैं। 1894 के भूमि अधिग्रहण अधिनियम से लेकर 2013 के LARR अधिनियम तक नीतियों में बदलाव हुए हैं, फिर भी पुनर्वास की प्रक्रिया अब भी लेन-देन और भौतिक मुआवज़े तक सीमित है। अध्ययन का मानना है कि ऐसे दृष्टिकोण लोगों की खोई हुई क्षमताओं—अर्थात वे वास्तविक स्वतंत्रताएँ जो उन्हें अपने मूल्यवान जीवन जीने में सक्षम बनाती हैं—को पुनर्स्थापित करने में विफल रहते हैं, जिससे अन्याय और बहिष्कार जारी रहता है।

यह शोध मिश्रित पद्धति (Mixed Methods) पर आधारित है, जिसमें गुणात्मक (Qualitative) अध्ययन को प्रमुखता दी गई है। जम्मू और कश्मीर की दो प्रमुख जलविद्युत परियोजनाओं—बांदीपोरा में किशनगंगा बांध परियोजना और किश्तवाड़ जिले में पाकल डुल परियोजना—पर यह अध्ययन किया गया। इसमें 40 से अधिक लोगों के गहन साक्षात्कार, 15 अधिकारियों से बातचीत, 105 परिवारों का सर्वेक्षण, तथा नीतिगत दस्तावेज़ों और पुनर्वास योजनाओं का विश्लेषण शामिल है। 2022 से 2025 के बीच चरणबद्ध फील्डवर्क किया गया, जिसमें

अभिलेखीय शोध, विभिन्न हितधारकों का विश्लेषण और सामुदायिक स्तर की जांच के माध्यम से नीतियों, व्यवहार और लोगों के अनुभवों को जोड़ा गया।

मैदानी साक्ष्य दर्शाते हैं कि जम्मू और कश्मीर जैसे क्षेत्रों में पुनर्वास प्रक्रिया बिखरी हुई, नौकरशाही से संचालित और प्रभावित समुदायों की सामाजिक-स्थानिक वास्तविकताओं से काफी हद तक अनभिज्ञ है। विस्थापन केवल आजीविका और आवास को ही नहीं, बल्कि सामाजिक संबंधों, पर्यावरणीय जुड़ाव और मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। महिलाएँ और अन्य कमजोर समूह असमान रूप से अधिक बोझ उठाते हैं, जबकि निर्णय लेने की प्रक्रिया में उनकी भागीदारी अक्सर केवल औपचारिक और प्रतीकात्मक होती है। अध्ययन यह दिखाता है कि न्याय केवल इस बात पर निर्भर नहीं करता कि लोगों को क्या मिलता है, बल्कि इस पर भी कि वे कहाँ और किस प्रकार अपना जीवन दोबारा स्थापित कर सकते हैं।

हालाँकि पहले के शोध और नीतिगत रिपोर्टों में अधिक मानवीय और सहभागी पुनर्वास की आवश्यकता पर जोर दिया गया है, यह अध्ययन इस बात को स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि क्षमता-आधारित और स्थानिक दृष्टिकोण के माध्यम से न्याय को व्यवहार में कैसे लागू किया जा सकता है। यह दृष्टिकोण राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर विभिन्न विकास परियोजनाओं में उपयोगी हो सकता है